

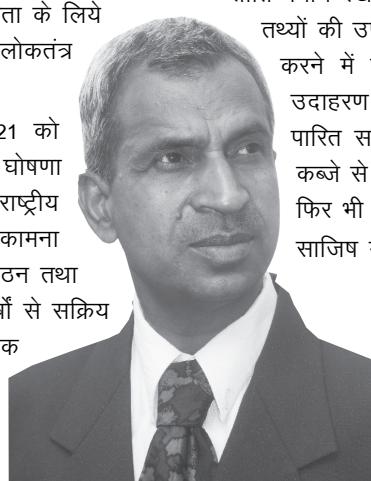
नवनिर्वाचित सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग का चीन के साथ

वार्ता पुनः प्रारंभ करने पर जोर

निर्वासित तिब्बत सरकार के नवनिर्वाचित सिक्योंग अर्थात् राजप्रमुख पेंपा त्सेरिंग द्वारा 27 मई, 2021 को कार्यभार संभालने के साथ ही चीन सरकार के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई है। अपने संबोधन में पेंपाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि तिब्बत समस्या का हल निकालने के लिये चीन के साथ वार्ता शीघ्र प्रारंभ करनी होगी। चीन सरकार अपने ही संविधान एवं राष्ट्रीयता कानून के अनुसार तिब्बत को “वास्तविक स्वायत्तता” प्रदान करे। प्रतिरक्षा तथा विदेश विभाग चीन के पास रहें। विक्षा एवं धर्म, संस्कृति समेत अन्य सभी विभाग तिब्बतियों को सौंपे जायें। इस व्यवस्था से चीन की एकता—अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। इससे तिब्बत को भी स्वचासन का अधिकार मिल जायेगा। इस व्यवस्था से तिब्बत एवं चीन समान रूप से लाभान्वित होंगे। इसी व्यवस्था को मिडल वे या “मध्यम मार्ग” कहा जाता है। निर्वासित तिब्बत सरकार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग छोड़कर तिब्बत के लिये केवल “वास्तविक स्वायत्तता” के पक्ष में है। चीन सरकार के साथ वार्ता का महत्वपूर्ण बिन्दु यही है।

लोकतांत्रिक तरीके से तिब्बती जनता द्वारा निर्वाचित नये सिक्योंग के शपथ—ग्रहण समारोह में परमपावन दलाई लामा द्वारा निवर्तमान सिक्योंग डॉ० लोबजंग संग्ये के तिब्बती संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की गई तथा नये सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग को सफलता हेतु शुभकामना दी गई। दलाई लामा का आषीर्वाद, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन तिब्बती संघर्ष को शांतिप्रिय एवं अहिंसक बनाये रखने के लिये जरूरी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहले स्वयंम् राजप्रमुख होते थे। लेकिन वर्तमान दलाई लामा ने तिब्बत एवं तिब्बतियों में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिये अपने समस्त राजनीतिक अधिकार तिब्बती जनता द्वारा मतदान के जरिये निर्वाचित तिब्बती संसद एवं सिक्योंग को एक दषक पहले ही सौंप चुके हैं। अब वे सिर्फ धार्मिक कार्यों तक ही स्वयंम् को सीमित कर चुके हैं। नवनिर्वाचित सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग का संकल्प इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाने का है। सरकार की कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका और अन्य समस्त संवैधानिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण जनता का सषक्तीकरण करेगा। तिब्बती जनता का, जनता के लिये तथा जनता द्वारा संचालित व्यवस्था ही तिब्बती लोकतंत्र का लक्ष्य है।

तिब्बती निर्वाचित आयोग द्वारा 14 मई, 2021 को नवनिर्वाचित सांसदों तथा सिक्योंग के नाम की घोषणा होते ही तिब्बतियों एवं तिब्बत समर्थकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसन्नता देखने को मिली। बधाई एवं शुभकामना देने वालों में विष्व के सभी लोकतांत्रिक देष, संगठन तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। तिब्बती संघर्ष में वर्षों से सक्रिय रहे तथा विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक दायित्व निभाने वाले पेंपा त्सेरिंग के प्रभावी कार्य व्यवहार का उन्हें पूरा विष्वास है। उनके द्वारा प्रेषित बधाई एवं शुभकामना से स्पष्ट है कि



तिब्बती संघर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन बढ़ता ही जा रहा है।

नवनिर्वाचित तिब्बती सांसदों एवं सिक्योंग के लिये उपयुक्त अवसर है कि वे दलाई लामा द्वारा 14 मई, 1989 को घोषित पंचेन लामा गेदुन चुकी नीमा की शीघ्र रिहाई हेतु चीन सरकार पर दबाव बढ़ायें। चीन सरकार ने 17 मई, 1989 को ही पंचेन लामा का सपरिवार अपहरण कर लिया था। चीन के बुहान से पूरे विष्व में फैलाई गई कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मई में ऑनलाईन आयोजन के जरिये साम्राज्यवादी चीन से अपील की गई है कि वह तिब्बतियों के धार्मिक मामले में अनुचित एवं अनावश्यक हस्तक्षेप करना बंद करे। इस विषय में निर्णय का अधिकार तिब्बती समुदाय तथा धर्मगुरुओं को है। दलाई लामा समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण धर्मगुरुओं के पुनर्जन्म का निर्णय सिर्फ तिब्बती परंपरानुसार किया जायेगा।

विष्व की संपूर्ण लोकतांत्रिक शवित्याँ तिब्बतियों के धार्मिक अदिकार के समर्थन में हैं, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत की नालंदा परंपरा में निहित हैं। इसी माह में दलाई लामा ने विभिन्न संस्थाओं को ऑनलाईन संबोधित करते हुए उन्हें शांति, अहिंसा, करुणा, प्रेम तथा सहयोग का वातावरण मजबूत करने की सलाह दी है। उन्हें वे नालंदा परंपरा के मानवीय मूल्य कहते हैं। वे सदैव इनके प्रचार—प्रसार में लगे रहते हैं। उनके ऐसे प्रयासों से ही तिब्बत का प्रब्लेम अन्तर्राष्ट्रीय प्रब्लेम बना हुआ है। नवनिर्वाचित तिब्बती सांसदों एवं सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग इर्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत करते हुए तिब्बती संघर्ष को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, ऐसा सभी तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों को विष्वास है।

लेकिन तिब्बती संघर्ष में सबसे बड़ी बाधा धर्मविरोधी साम्यवादी चीन की साम्राज्यवादी नीति है। अपनी विस्तारवादी तथा साजिष्पूर्ण नीति के अनुरूप चीन सरकार अपने सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय हितों को चोट पहुँचा रही है। गलवान घाटी में चीन को करारा जवाब देने के बाद भारत सरकार लगातार चीन के साथ वार्ता कर रही है। भारत सीमा पर शांति बनाये रखने के पक्ष में है, लेकिन चीन सरकार शांति वार्ता में तय तथ्यों की उपेक्षा करते हुए सीमा पर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने में लगी है। यह कूटनीतिक विष्वासघात का अस्वीकार्य उदाहरण है। चीन को भारतीय संसद द्वारा 14 नवंबर, 1962 को पारित सर्वसम्मत संकल्प की पूरी जानकारी है जिसमें चीन के कब्जे से भारतीय भूमाल को मुक्त कराने का प्रण लिया गया है। फिर भी चीन सरकार भारत के नये—नये क्षेत्रों को हथियाने की साजिष्प में लगी है। ◆

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
मो. & 9829806065, 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

क्रिएटिंग होप-पिको अय्यर के साथ बातचीत

dalailama.com, 19 मई, 2021



परम पवन दलाई लामा पिको अय्यर के साथ वेबिनेर में जुड़े।

थेकछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज 19 मई की सुबह परम पावन दलाई लामा जब मुस्कुराते और हाथ लहराते हुए कैमरों के सामने अपने आसन पर विराजमान हो गए तब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा (यूसीएसबी) में कला और व्याख्यान की कार्यकारी निदेशक सेलेस्टा बिलेसी ने इस अवसर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 'हम एक ऐसे क्षण में रह रहे हैं जिसमें आशावाद, लचीलापन, साहस और दृष्टि की अधिक जरूरत है। और इन गुणों को हमारे अंदर जगाने के लिए दलाई लामा से बेहतर कौन हो सकता है?' विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हेनरी यांग ने अतिथियों का स्वागत किया और परम पावन को संबोधित करते हुए उद्घोषणा की, 'आज आपका स्वागत करना हमारे लिए असाधारण सम्मान की बात है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे परम पावन दलाई लामा के इन आशावादी संदेश को आपके सामने रखने में प्रसन्नता हो रही है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम परम पावन का यहां पांचवीं बार स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम 14वें दलाई लामा पीठ की स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं। दलाई लामा एक अतुलनीय बौद्ध शिक्षक और सुलह के चौपियन हैं। वह करुणा और शांति की प्रतिमूर्ति हैं।'

इसके साथ ही उन्होंने पिको अय्यर को परम पावन के साथ बात चीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया।

पिको अय्यर : आपका स्वागत है परम पावन। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। अब हम अपना ध्यान 'उम्मीद' पर केंद्रित कर रहे हैं। बौद्धों के लिए 'उम्मीद' का क्या अर्थ है?

परम पावन : इसे सीधे शब्दों में कहें तो हमारा जीवन चीजों को अच्छी तरह से बदलने की इच्छा से संबंधित उम्मीदों पर आधारित है। गर्भ में भी मां की मन की शांति शिशु को प्रभावित करती है। उम्मीद का संबंध भविष्य से है। हालांकि, भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हम आशान्वित रहते हैं जो निराशावादी होने से कहीं बेहतर है। वैश्विक स्तर पर भी हमारे पास उम्मीदों के लिए आधार है।

उन्होंने कहा, 'हम सब अपनी मां से ही जन्म लेते हैं। हम उसकी देखरेख में बढ़ते हैं। उनकी करुणा और दया की सराहना करना, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते थे, एक आधार है जिसमें करुणा को देखा जा सकता है। मां की कृपा का अनुभव हमें उम्मीद बंधाता है।'

'मुझे लगता है कि जिन बच्चों की मां बचपन में गुजर जाती हैं, अगर हम उन बच्चों के बारे में जानने समझने की कोशिश करें तो कुछ भावनात्मक चीजें सीखने को मिलेंगी।'

'हमारा जीवन उम्मीदों पर टिका है। यदि आप उम्मीदों के सहारे हैं, तो आप अपने सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आप उम्मीदों से रहित हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।' उम्मीद करुणा और प्रेमपूर्ण दया से जुड़ी हुई है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अपने जीवन में हर तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके अलावा, सच्चा और ईमानदार होना भी उम्मीद और आत्मविश्वास का आधार है। सच्चा और ईमानदार होना झूठी उम्मीदों का प्रतिकार है। सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित आशा मजबूत और शक्तिशाली होती है।

पिको अय्यर: क्या हम अपनी उम्मीदों के बारे में अधिक यथार्थवादी होने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं?

परम पावन : हमारा मानव मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमें केवल हमारी तात्कालिक जरूरतों के बारे में न सोचकर, दीर्घकालिक हितों के बारे में सोचने के लिए सक्षम बनाती है। हम एक व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि हमारे दीर्घकालिक हित क्या है। उदाहरण के लिए, बौद्ध साधना के संदर्भ में हम युगों-युगों के बारे में बात करते हैं और सभी भव्य प्राणियों की सेवा करते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है।

पिको अय्यर : क्या उम्मीद का संबंध धर्म से नहीं है?

परम पावन : आम तौर पर, धर्म आस्था का सवाल है, लेकिन जब हम अपनी मां के स्नेह में डूब जाते हैं, तो इसमें कोई आस्था का सवाल नहीं होता है। आस्था एक ऐसी चीज है जिसे इसानों ने बनाया है। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं दया और प्रेम के महत्व को सिखाती हैं। कुछ कहते हैं कि एक ईश्वर है, दूसरे इसे नकारते हैं। कुछ कहते हैं कि हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल एक ही जन्म तक रहते हैं। ये परंपराएं विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती हैं, लेकिन वे प्रेमपूर्ण दयालुता का संदेश देने में एकसमान हैं।

ईसाई धर्म जैसी आस्तिक परंपराएं सिखाती हैं कि हम सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जो एक पिता की तरह अनंत प्रेम का प्रतीक है। यह एक प्रभावी विचार है जो हमें दयालु होने के महत्व को पहचानने में मदद कर सकता है।

'हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने समुदाय पर आश्रित हैं। एक समुदाय के सदस्य के रूप में यहां तक कि बिना आस्था या विश्वास वाले लोग भी विचारशील, सच्चे और ईमानदार होकर अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। ईमानदार और करुणामय होना जरूरी नहीं कि धार्मिक गुण हों, लेकिन वे हमें सुखी जीवन जीने में योगदान करते हैं। अपने समुदाय के बारे में चिंतित होना हमारे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। प्रमुख कारक करुणा है। क्रोध इसके विपरीत है। क्रोध सुख और सद्भाव को नष्ट कर देता है।'

'हमें मानवता की एकता की भावना को विकसित करने की जरूरत है। इसीलिए मैं इसके बारे में बातें करता हूं और मैं जहां भी जाता हूं और जिससे भी मिलता हूं मैं उसे एक भाई या बहन के तौर पर एक और इंसान के रूप में मानता हूं। हम सात अरब मनुष्य अनिवार्य रूप से एक जैसे हैं। हमारे बीच राष्ट्रीयता, रंग, आस्था और सामाजिक स्थिति में अंतर तो है, लेकिन केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना अपने लिए समस्याएं पैदा करना है।'

कल्पना कीजिए कि आप किसी आपदा से बच गए हैं और अपने

आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। यदि आप किसी को दूर से आते हुए देखते हैं, तो आपको उनकी राष्ट्रीयता, जाति या धर्म की परवाह नहीं होगी, आपको किसी अन्य इंसान से मिलकर खुशी होगी। विकट परिस्थितियां हमें मानवता की एकता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

अतीत में बहुत सारी युद्ध और हिंसा हुई हैं। आजकल जब जलवायु संकट के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है तो हमें एक-दूसरे की मदद करनी पड़ती है। जब तक हम रह सकते हैं, हमें खुशी-खुशी एक साथ रहने का प्रयास करना होगा।

पिको अध्यर: आपने ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया है। ऐसी चुनौती का सामना करने में हम आशान्वित कैसे रह सकते हैं?

परम पावन : ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यों के बीच विवाद न करने का एक अच्छा कारण है। हमें साथ रहना सीखना चाहिए। हम सभी इंसान हैं और हम सभी इस एक ग्रह पर रह रहे हैं। हम केवल 'मेरा देश', 'मेरा समुदाय' की सोच रखकर पुराने रुख पर टिके नहीं रह सकते हैं, हमें पूरी मानवता का ध्यान रखना होगा।

पिको अध्यर: क्या आपको कभी उम्मीद खोने की चिंता हुई है?

परम पावन : 'केवल 17 मार्च 1959 को जब मैं ल्हासा छोड़ रहा था। मैं वास्तव में सोच रहा था कि क्या मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। फिर, अगली सुबह सूरज उग आया और मैंने सोचा, 'मैं बच गया।' चीनी जनरलों में से एक को यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि दलाई लामा नोरबुलिंगका में कहाँ रुके हुए हैं, ताकि वे उस पर गोलाबारी से बच सकें। मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में मेरी रक्षा करना चाहता था या मुझे निशाना बनाना चाहता था। उस अवसर पर मुझे कुछ घबराहट महसूस हुई।'

'अगले दिन, जब हम चे—ला दर्द पर पहुँचे, तो मेरे घोड़े के साईस ने मुझे बताया कि यह आखिरी जगह है, जहां से हम पोटाला पैलेस और ल्हासा शहर को देख सकते हैं। उसने मेरा घोड़ा घुमाया ताकि मैं आखिरी बार देख सकूँ।'

आखिरकार हम भारत पहुँचे, जो हमारे सभी ज्ञान का स्रोत है और जहां सीखने के लिए नालंदा विचारधारा है। मैं बचपन से ही तर्क और कारण के अनुप्रयोग के साथ अनुसंधान की इस परंपरा में डूबा हुआ था। तर्क में निहित आरथा मजबूत है। अन्यथा यह नाजुक है।

आज, वैज्ञानिक हमारे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के कायल हो रहे हैं, जो हमारी चर्चाओं के लिए आधार प्रदान करता है। इसके अलावा, हम विश्लेषण के परिणामस्वरूप मन को एकाग्र और शांत करने के लिए समता और विपश्यना की साधना करते हैं। इन गुणों के अलावा हम—अहिंसा और करुणा—को तर्क के आधार पर विकसित करते हैं।'

पिको अध्यर: कोविड महामारी से कई लोग प्रभावित हुए हैं। हम मृत्यु और नुकसान से कैसे निपट सकते हैं?

परम पावन : 'मैं वास्तव में उन सभी डॉक्टरों और नर्सों के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने बीमार लोगों की मदद की है और कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'एक बौद्ध के रूप में मैं इस शरीर को इस रूप में देखता हूं जो हमें बीमार बनाने की ओर प्रवृत्त करती है।' लेकिन मन की शांति बनाए रखने से अलग बात हो जाती है। चिंता बस चीजों को और खराब करती है। यदि आपका मन शांत है और आप स्वीकार कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों के परिणामस्वरूप बीमार पड़ते हैं, तो यह आपकी मदद कर सकता है।'

पिको अध्यर: परम पावन, आपको युवाओं पर बहुत विश्वास है। क्या वे आपकी उम्मीदों का आधार हैं?

परम पावन : बुजुर्ग लोग वे लकीर के फकीर होते हैं, वहीं करते हैं

जो परंपरा से होती आ रही है। युवा लोग अधिक खुले विचार के होते हैं, मन में अधिक रुचि रखते हैं। आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति पश्चिम में हुई है, लेकिन प्राचीन भारत ने मन और भावनाओं के कामकाज की व्यापक समझ विकसित की है। प्राचीन भारत ने पचास से अधिक प्रकार की भावनाओं को रेखांकित किया। मेरा मानना है कि भारत आज आधुनिक शिक्षा की भौतिकवादी सोच को विनाशकारी भावनाओं से निपटने की समझ के साथ जोड़ सकता है।'

पिको अध्यर : एक सामान्य व्यक्ति मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है?

परम पावन : भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, मेरा मानना है कि इसे मन के कामकाज की प्राचीन भारतीय समझ और मानसिक शांति प्राप्त करने के धर्मनिरपेक्ष तरीकों के साथ उपयोगी रूप से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, इसे विनाशकारी भावनाओं से निपटने के तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। जब महामारी खत्म हो जाएगी, मैं भारतीय शिक्षकों के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं कि यह कैसे किया जा सकता है।'

पिको अध्यर : जब आप लगभग 86 साल पहले पैदा हुए थे, क्या दुनिया तब से बेहतर हुई है?

परम पावन : लोग अपने ही किए कार्यों या चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वर्तमान की कोरोना महामारी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं द्वारा पेश की जा रही चुनौतियां हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। कठिनाइयां हमारा दिमाग खोल सकती हैं और हमारी बुद्धि को उनसे निपटने में लगा सकती है। भारतीय बौद्ध आचार्य शांतिदेव ने हमें बताया है कि हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का परीक्षण करके देखें कि क्या उनका समाधान किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो हमें यही करना होगा। चिंता करने से मदद नहीं मिलेगी। चुनौतियां हमें जगा सकती हैं।

युवा पीढ़ी अधिक खुले विचारों वाली होती है, जबकि बुजुर्ग लोग स्थापित मान्यताओं से चिपके रहते हैं। लेकिन युवा लोग ही समस्याओं पर काबू पाने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएंगे।'

पिको अध्यर : कुछ लोगों को चिंता है कि आज दुनिया में गुस्सा और हिंसा बढ़ रही है। क्या आप इससे सहमत हैं या आप फिर भी आशान्वित हैं?

परम पावन : 'पिछली सदी में इतना खून—खराबा हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूर्व दुश्मनों—ऐडेनॉयर और डी गॉल ने यूरोपीय संघ की स्थापना की। तब से इसके सदस्य देशों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। पूरी दुनिया को पूरी मानवता की भलाई के लिए चिंता का ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। संघर्ष और कठिन परिस्थितियां हमें सोचने के पुराने तरीकों—उदाहरण के लिए बल प्रयोग जैसे उपाय—की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन हमें एक नया और अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।'

'मुझे लगता है कि अगर मैं ल्हासा में रहता, तो मैं जितना सोचता हूं उससे कहीं संकीर्ण दिमाग से सोचता। शरणार्थी के रूप में भारत आने से मेरा दिमाग खुला और विस्तृत हुआ है और इस परिस्थिति ने मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है।'

पिको अध्यर: हम तिब्बत की मदद कैसे कर सकते हैं और तिब्बती संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

परम पावन : '2001 से मैं राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूं। लेकिन मैं अभी भी तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी महसूस करता हूं। आठवीं शताब्दी में तिब्बती सम्मान ने शांतरक्षित को

आमंत्रित किया, जो एक महान दार्शनिक और उसी रूप में महान तर्कशास्त्री थे। उन्होंने नालंदा परंपरा की शुरुआत की, जिसमें वैज्ञानिक सोच के साथ बहुत कुछ है। यह एक तार्किक, खोजी वृष्टिकोण अपनाने पर आधारित है।'

उस समय तिब्बत में चीनी बौद्ध शिक्षक थे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि ध्यान का अभ्यास अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण था। शांतरक्षित के शिष्य कमलशील ने समाट के समक्ष चीनी और भारतीय वृष्टिकोण के गुणों को लेकर शास्त्रार्थ किया। भारतीय परंपरा की जीत हुई हुई और चीनी शिक्षकों को चीन लौट जाने के लिए कह दिया गया। तब से हमने तर्क को अपनाया है। कारण, तर्क और ज्ञानमीमांसा पर प्रमुख भारतीय ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद किया गया। यही नालंदा परंपरा की नींव है, जिसे हमने जीवित रखा है।

'आजकल तिब्बत के सुदूर भागों में चीनी कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध करने के प्रयासों के बावजूद इन परंपराओं का अध्ययन जारी है। भारत में हमने अपने प्रमुख शिक्षा केंद्रों को फिर से स्थापित किया है और 10,000 से अधिक मठवासी कठोर अध्ययन में लगे हुए हैं।'

पिको अर्थर: क्या आप भावनात्मक स्वच्छता की व्याख्या कर सकते हैं?

परम पावन : 'उदाहरण के तौर पर इसमें यह स्वीकारोक्ति है कि मन की शांति का सबसे प्रभावी विध्यंसक क्रोध है। लेकिन उस क्रोध का मुकाबला दूसरों के लिए परोपकारिता और करुणा विकसित करके किया जा सकता है। एक और मानसिक पीड़ा अज्ञानता है जो हमारे लिए समस्याएं खड़ी करती है। इसे अध्ययन से कम किया जा सकता है। एक महान तिब्बती विद्वान ने एक बार टिप्पणी की थी कि भले ही मुझे कल मरना हो, फिर भी मैं आज भी अध्ययन ही करूंगा।'

पिको अर्थर: क्या चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ रही है?

परम पावन : हाँ, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच भी। हमने 'सा. इंस एंड किलॉसफी इन द इंडियन बुद्धिस्ट कलासिक्स' शीर्षक शृंखला के कई खंड प्रकाशित किए हैं और चीनी अनुवाद उन तक पहुंच चुके

हैं। नतीजतन, उन्होंने हमारी परंपरा की अधिक प्रशंसा की है। शायद वे देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा मार्क्सवादी अधिनायकवाद से कहीं अधिक गहरी है।'

पिको अर्थर: क्या आप कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के छात्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे?

परम पावन : 'यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। हमारा भविष्य शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। हमें नया ज्ञान चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर शोध कर सकें और जो कुछ वे सीखते हैं उसे अपने छात्रों को दे सकें। एक बेहतर दुनिया बनाने की हमारी क्षमता में यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। धन्यवाद।'

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष माइकल ड्रेक ने अपना समय देने के लिए परम पावन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि परम पावन यूसीएसबी के साथ 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 20 साल पहले यहां तिब्बती अध्ययन के लिए 14वें दलाई लामा पीठ की स्थापना हुई थी। उन्होंने बातचीत करने के लिए पिको अर्थर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज जीवित सभी सात अरब मनुष्यों के जीवन में करुणा महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चांसलर यांग और सेलेस्टा बिलेसी को धन्यवाद दिया गया और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

परम पावन ने अपनी ओर से धन्यवाद और सुझाव देने के साथ उत्तर दिया कि समय—समय पर इंटरनेट पर आज की तरह आगे की बातचीत करना संभव होगा। 'दुनिया की बेहतरी के लिए मैं जो भी योगदान दे सकता हूं, वह करना मेरा कर्तव्य है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। हमारे जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है।'

सेलेस्टा बिलेसी ने परम पावन, पिको अर्थर और अध्यक्ष ड्रेक को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए सत्र समाप्त किया और आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय की पहल 'क्रिएटिंग होप' से दूसरों को लाभ होगा। उन्होंने परम पावन को उद्धृत करते हुए निष्कर्ष निकाला: 'जब भी संभव हो दयालु बनें, यह हमेशा संभव है।' ◆

सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि

dalailama.com, 22 मई, 2021



रवर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा।

थेकछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज 22 मई को अपने कार्यालय द्वारा जारी एक संदेश में परम पावन दलाई लामा ने यह जानकर दुख व्यक्त किया है कि उनके अच्छे मित्र श्री सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने लिखा, 'मैं उनके परिवार के साथ—साथ उनके कई प्रशंसकों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा।'

'जिस तरह से उन्होंने 'अहिंसा' को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने

अधक अभियानों का मूल बनाया, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता रहा हूं। उत्तराखण्ड के गढ़वाल में पले—बढ़े वे न केवल हिमालयी क्षेत्र की नदियों, जंगलों और पहाड़ियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते थे, बल्कि उन्हें लगा कि अन्य लोगों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना उनका मिशन है।

'एक बार बहुगुणा ने मुझे पेड़ लगाने और जब भी संभव हो उनकी देखभाल करने के महत्व के बारे में प्रचार करने के लिए कहा। मैं ऐसा करने के लिए सहमत हो गया और जब मैं लद्धाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य जगहों का दौरा करता हूं तो मैं लोगों से पर्यावरण की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता हूं, जिसका प्रभाव उनके रहने के क्षेत्रों से कहीं अधिक बड़े इलाके प्रभाव पड़ता है।'

परम पावन ने अपने शोक संदेश के अंत में लिखा है, 'यद्यपि उन्होंने एक लंबा और सार्थक जीवन व्यतीत करते हुए, हमें छोड़ दिया है, श्री बहुगुणा की आत्मा जीवित रहेगी। उनके प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम उन्हें दे सकते हैं, वह उस आंदोलन का समर्थन करना जारी रखना होगा जो उन्होंने पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और हमारी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए शुरू किया था।' ◆

सिक्योंग पेब्या ल्सेरिंग का उद्घाटन भाषण

27 मई 2021



सिक्योंग (राष्ट्रपति) पेब्या सेरिंग का उद्घाटन भाषण।

आज प्रातः शपथ ग्रहण के बाद परम पावन दलाई लामा की आभासी उपस्थिति में आयोजित उद्घाटन समारोह में उनका आशीर्वाद पाकर हम अपने को बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी तिब्बती परम पावन के मार्गदर्शन में चलते हैं। हमारी कार्यपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी कि हम परम पावन दलाई लामा द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें और उसके अनुसार कार्य करें। सबसे पहले मैं तिब्बत के लोगों के रक्षक प्रतीक परम पावन दलाई लामा और धर्म के अन्य सभी प्रतिष्ठित धारकों के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा अर्पित करता हूं। साथ ही मैं तिब्बत के भीतर और बाहर रहनेवाले अपने सभी तिब्बती भाइयों—बहनों और सभी रखतंत्रता और सत्य प्रेरी तिब्बत समर्थकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, विदेश विभाग, ताइवान के विदेश मंत्री, तिब्बत के संसदीय मित्रों के साथ ही दुनिया भर से तिब्बत समर्थक समूहों, संगठनों और व्यक्तियों से मिले असंख्य हार्दिक बधाई पत्रों के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

1. इस अवसर पर मैं तिब्बती लोगों द्वारा 16वीं काशाग के लिए पांच वर्षों कालोन द्विपाधिक्योंग और निर्वासित 17वीं तिब्बती संसद के चुनाव के सफल संचालन का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि निर्वासित तिब्बतियों के बीच लोकतांत्रिक राजनीति के बीच विवादों के सम्बन्ध में विजयी कदम के रूप में देखा जा सकता है और यह जीत प्रशासन और आम जनता के संयुक्त प्रयास के कारण है।

2. इस चुनाव के दौरान निर्वासित तिब्बतियों की 77: पंजीकृत मत दाताओं की भागीदारी और समग्र चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन को लोकतांत्रिक राजनीति में विजयी कदम के रूप में देखा जा सकता है और यह जीत प्रशासन और आम जनता के संयुक्त प्रयास के कारण है।

3. इस चुनाव में आम जनता ने जो विश्वास जताया है और उम्मीदें पाल रखी हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं चीन—तिब्बत संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने और तिब्बती लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। मैंने अपनी आभासी प्रस्तुतियों के दौरान जिन विचारों को प्रचारित किया है और जो बातें मेरे घोषणा—पत्र में कही गई हैं, वे कई वर्षों की सार्वजनिक सेवा के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर हैं और तिब्बत, चीन और विश्व स्तर पर लगातार बदलती परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और समीक्षा करने के बाद प्रस्तुत किए गए हैं। मैंने उन नीतियों और कार्यक्रमों को तड़े दिल से पेश करने की कोशिश

की है, जिनकी जरूरत है, जो किया जाना चाहिए और जो किया जा सकता है। सर्वोच्च न्याय आयोग के कार्यालय के लिखित निर्देश के अनुसार, मैंने आज सुबह सर्वोच्च न्याय आयुक्त के समक्ष जो शपथ ली है, उसके अनुसार मैं चार्टर पर विश्वास करता हूं और उससे बंधा रहूंगा और चार्टर के प्रावधानों का किसी तरह के स्वार्थ, पूर्वाग्रह, भय और पक्षपात से रहित होकर न्यायपूर्ण तरीके से किसी दिखावे से परे अच्छे इरादे से जिम्मेदारी पूर्वक अनुपालन करूंगा।

चीन—तिब्बत संघर्ष का समाधान

1. काशाग की मुख्य जिम्मेदारी संकटग्रस्त तिब्बत और तिब्बती लोगों के सामने आने वाली कठिन चुनौतियों से राहत पाना है। हम परम पावन दलाई लामा द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे, जिसे तिब्बत के अंदर और बाहर के तिब्बतियों का बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त है और जिसका अनुभोदन निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा सर्वसम्मति से किया गया है। इसके आधार पर हम चीन सरकार के साथ बातचीत के जरिए चीन—तिब्बत संघर्ष का पारस्परिक रूप से लाभकारी, अहिंसक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह मध्यम मार्ग दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा।

2. जब तक इस तरह का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, हम तिब्बत में रहनेवाले तिब्बतियों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और हर एक तिब्बती के संसाधन को एकत्रित करके अपने लिए वैशिक समर्थन को और मजबूत करेंगे। हम पर्यावरण के विनाश और तिब्बत के भीतर तिब्बती राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण से संबंधित बुनियादी मुद्दों पर नजर रखेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। हम चीनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में बड़ी गलतियों को इंगित करने से पीछे नहीं हटेंगे और गलत नीतियों को सुधारने, वापस लेने या संशोधित करने के लिए दबाव डालने का प्रयास करेंगे। इसी तरह हम तिब्बत में रहनेवाले तिब्बतियों और निर्वासित तिब्बतियों के बीच अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और परम पावन दलाई लामा की चीन यात्रा की इच्छा को साकार करने की दिशा में काम करेंगे।

3. भविष्य में यदि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण में नवीनता लाने की आवश्यकता होगी, तो हम संबंधित निकायों से परामर्श करेंगे और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार निर्णय लेंगे।

4. भारत, अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए हमारी कार्यपालिका उचित विचार, लगन और दृढ़ता का सहारा लेगा।

5. चीनी सरकार ने इस महीने की 21 तारीख को एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक '1951' के बाद तिब्बत की मुक्ति, विकास और समृद्धि है। मैं आज केवल इन तारीखों के बारे में कहता हूं कि हम श्वेत पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए लोगों को भेजने के लिए तैयार हैं।

लोकतांत्रिक राजनीति का सशक्तिकरण

1. निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर की प्रस्तावना में निर्वासन में आने के बाद से तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा की लंबे समय से पोषित दृष्टि के अनुरूप शासन को लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर ले जाने और उसके बाद के घटनाक्रमों के विकास को रेखांकित किया गया है। सत्ता का तीन अंगों के बीच सार्थक विभाजन समझ और संतुलन

को दिखाता है जो मजबूत और जीवंत लोकतंत्र का आधार है। इसलिए, चार्टर के सार के अनुसार, काशाग सर्वोच्च न्याय आयोग को उचित सम्मान और गरिमा प्रदान करेगा और न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

क. निर्वासित तिब्बती संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगी और विधान के सभी कार्यक्रमों का समर्थन करेगी।

ख. तीनों स्वायत्त निकायों को उनकी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखते हुए उनके प्रगतिशील कामकाज के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

ग. मीडिया की स्वतंत्रता और गरिमा को कायम रखते हुए उसे सार्थक चौथा स्तंभ बनने में मदद करेगी।

घ. गैर-सरकारी संगठनों के साथ उनके क्षेत्र, धार्मिक परंपरा या राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए हमारे प्रयासों को मजबूत करने के लिए काम करेगी।

ड. सभी सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित सभी जमीनी संगठनों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और आम जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह रहेंगी।

कार्यपालिका के कार्य

1. कार्यपालिका का पहला काम सभी मंत्रियों और अधिकारियों को यह स्पष्ट करना है कि हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं और उन्हें इस प्राथमिक उद्देश्य से विचलित न होने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2. काशाग नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयास में वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए सिविल सेवकों के अनुभव को उचित महत्व देगा।

3. परम पावन दलाई लामा और मठों के प्रमुखों के मार्गदर्शन के अनुसार, कार्यपालिका सभी मठ संस्थाओं को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी चाहे वे तिब्बती धर्म और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से संबद्ध हों या नहीं।

4. औचित्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों के एकीकरण और छात्रों के अध्ययन के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करने में छात्रों की रुचि को प्रमुखता दी जाएगी।

5. तिब्बती समुदायों के विकास और उचित कामकाज के लिए गरीबों और जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम की प्रकृति के आधार पर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऊपर से नीचे की ओर का कार्यक्रम या नीचे से ऊपर की ओर जाता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

6. लोगों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के महत्व को बनाए रखते हुए समुचित स्वास्थ्य देखभाल और बीमारों और वृद्धों को उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा।

7. प्रशासन और आम जनता की वित्तीय निरंतरता को बनाए रखने के लिए उद्यम की सुविधा, कौशल और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए बस्ती के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के बीच व्यापक सहयोग के अलावा सुनियोजित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. समुदाय के व्यापक हित को देखते हुए तिब्बती बुद्धिजीवियों और युवाओं की क्षमता और योग्यता का समुचित उपयोग करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

9. सिक्योंग मुख्य रूप से चीन-तिब्बत संघर्ष को सुलझाने, सरकारों तक पहुंचने और प्रशासन और जनता के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने पर काम करेंगे।

10. मंत्री अपने पोर्टफोलियो के अनुसार, अपना काम पूरा करेंगे और जैसा कि कहा गया है, परम पावन दलाई लामा के प्रति जिम्मेदारियों

को निभाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे।

11. अच्छी तरह से निर्धारित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुदाय के बीच व्यापक समझ का होना अनिवार्य है। इसलिए, जनसांख्यिकीय जनगणना जल्द से जल्द शुरू की जाएगी।

अपील और अनुरोध

1. उच्च स्तर पर लड़े गए लोकतांत्रिक चुनावों में मतभेद होना स्वाभाविक है। हालांकि, व्यक्तिगत पूर्वग्रहों को सार्वजनिक स्तर पर मतभेद का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और इसी तरह, सार्वजनिक मामलों में मतभेदों के आधार पर व्यक्तिगत द्वेष नहीं पालना चाहिए। हमें अपने सच्चे प्रतिद्वंद्वी को खोजना चाहिए और पहचानना चाहिए। हमने अपना देश खो दिया और राजनीतिक शरणार्थी हैं। हम सभी चीन-तिब्बत संघर्ष को सुलझाने के सामूहिक लक्ष्य को लेकर चलते हैं। समुदाय के भीतर मुद्दों और विवादों को हल करने के लिए हमारे पास मानदंड, नियम और विनियम निर्धारित हैं। कार्यपालिका न केवल अभियक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करेगी और उचित राय सुनेगी बल्कि उचित प्रतिक्रिया भी देगी। मैं आम जनता से बेहतर सहयोग और जिम्मेदारी के लिए दिल से अनुरोध करता हूं।

2. जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि हम कानून के शासन को बनाए रखते हुए समान न्याय के तत्वों, हममें से प्रत्येक के सहकारी प्रयास और प्रगतिशील भविष्य के उद्देश्य से आगे बढ़ने के उद्देश्य को पूरा करने के चरण में पहुंच जाते हैं, तो हम चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने और अपने समुदाय के कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की सही दिशा में आगे बढ़ने को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम संघर्ष की राह में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

3. इस महीने की 23 तारीख को तिब्बत के गोलोग क्षेत्र को भीषण भूकंप ने हिला कर रख दिया था। हम उन सभी तिब्बतियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण घायल हुए हैं या अपनी संपत्ति खो चुके हैं।

4. प्रशासन को प्राथमिकता के तौर पर यह देखना होगा कि भारत और नेपाल में तिब्बती समुदायों के भीतर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। हम केंद्र और स्थानीय दोनों स्तरों पर कोविड टास्क फोर्स की संरचना की समीक्षा करेंगे और हर संभव उपचारात्मक उपाय करेंगे। मैं दो दिनों में इस पर बयान जारी करूंगा और प्रशासन द्वारा उपचारात्मक उपायों और दिशा-निर्देशों के बारे में बताऊंगा।

5. सक्षेप में, मैं इस अवसर पर दुनिया भर की सभी स्वतंत्रता-प्रेरी सरकारों, संसदों और तिब्बत समर्थकों और विशेष रूप से भारत और अमेरिका को तिब्बत और तिब्बती लोगों के प्रति अब तक दर्शाए गए प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका समर्थन तिब्बत में और निर्वासन में हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, तब तक आप हमारे प्रति अपना समर्थन बनाएं रखें।

6. अंत में, परम पावन दीर्घायु हों और उनकी सभी मनोकामनाएं सहजता से पूरी हों। वह दिन जल्द आए, जब तिब्बत में रहनेवाले तिब्बती और निर्वासित तिब्बती आपस में फिर से मिलें और आनन्दित हों। ◆

पेन्या त्सेरिंग
सिक्योंग

सीसीपी की राजनीतिक 'पुनः शिक्षा' का विरोध करने वाले ४४ बच्चों के तिब्बती पिता की 2019 में यातना से मौत

tibet.net, 05 मई, 2021



नोरसँग की तस्वीर।

धर्मशाला। तिब्बती खाम प्रांत के पारंपरिक शग रोंगपो क्षेत्र में तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र नागचू (चीनी: नाकू) का उत्तरी केंद्र टाउनशिप में जबरन राजनीतिक पुनः शिक्षा अभियानों में भाग लेने से इनकार करने पर 2019 में हिरासत में लिए गए एक तिब्बती व्यक्ति की चीनी पुलिस की हिरासत में पीटे जाने के बाद मौत हो गई। एक सूत्र ने इस बात की सूचना दी है।

लगभग 36 वर्षीय नोरसांग का 2019 में पुलिस हिरासत में पिटाई और प्रताड़ना के कारण मौत हो गई। चीनी अधिकारियों ने शुरू में उन्हें सितंबर 2019 के अंत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) शासन की 70 वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले शग रोंगपो के त्साल्ही गांव से कई अन्य तिब्बतियों के साथ हिरासत में लिया था। स्थानीय अधिकारियों द्वारा नागरिक अशांति या सीसीपी के संवेदनशील कार्यक्रम से पहले विद्रोह के किसी भी खतरे से निपटने के प्रयास में उन्हें बड़े पैमाने पर राजनीतिक पुनः शिक्षा अभियान या देशभक्तिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा गया था। बाद में, अधिकारियों ने अन्य को रिहा कर दिया लेकिन नोरसांग को हिरासत में ही रखा। उनके परिवार के सदस्यों को उनके पास जाने से मना कर दिया गया था, जिससे उनकी सेहत के लिए डर बढ़ रहा था।

शग रोंगपो क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों में लगाए गए ऑनलाइन संचार पर चीन के उच्च प्रतिबंध के कारण नोरसांग की मृत्यु अब तक तिब्बत के बाहर की दुनिया के लिए अज्ञात बनी हुई थी।

सूत्र ने कहा, 'चीनी अधिकारियों ने उनके परिवार और उनके गांव के निवासियों को उनकी मौत के बारे में कुछ भी जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रखी थी।'

मौत की जिम्मेदारी से साफ—साफ बचने के प्रयास में चीनी अधिकारियों ने कहा कि कर्ज के बोझ के कारण नोरसांग ने शगचू ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन स्थानीय निवासियों ने चीनी

बयान का उपहास उड़ाते हुए कहा कि नोरसांग के नाम पर एक भी कर्ज नहीं था और वह गांव का संपन्न व्यक्ति माना जाता था। चीनी बयान जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। ग्रामीणों का मानना है कि उसकी मौत का कारण चीनी अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर पिटाई और प्रताड़ना है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चीनी पुलिस के हाथों प्रताड़ना और दूर्योगहार से बचने के लिए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पुल से छलांग लगा ली होगी। यह कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा कारण सही है। क्योंकि चीनी अधिकारियों ने किसी भी ग्रामीण को उसके शव को देखने या उसके करीब आने से रोक दिया था।

उनके निधन के बाद कई दिनों तक अधिकारियों ने गेसो सबा गांव में उनके घर को घेरे रखना और तलाशी लेना जारी रखा। इस प्रक्रिया में उनकी गर्भवती पत्नी और परिवार ने भी विरोध किया। स्थानीय लोगों ने उस समय कई दिनों तक क्षेत्र के आसपास पुलिस वाहनों को आते-जाते देखा है। नोरसांग के निधन की खबर और पुलिस की लगातार व्यवस्थित तलाशी उसकी पत्नी के मानसिक उत्तीर्ण और आघात का कारण बना जिसने संभवतः उन्हें अस्थिर मानसिक स्थिति में डाल दिया। घटना के बाद से उनके परिवार की स्थिति और खराब हो गई है और वे वर्तमान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं।

हमारे सूत्र के अनुसार, नोरसांग परम पावन दलाई लामा के प्रति प्रबल श्रद्धा के साथ तिब्बती राष्ट्रीयता के जबरदस्त समर्थक थे। वह एक ऐसे दृढ़ रुख वाले व्यक्ति थे, जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार अभियानों की नीतियों को स्वीकार करने और उनका पालन करने से इनकार कर दिया। इसमें पार्टी के काम की प्रशंसा करना, घर पर पांच चीनी नेताओं की फ्रेम्युक्त तस्वीर को अनिवार्य रूप से लटकाना और चीनी झंडे को अनिवार्य तौर पर फहराना शामिल है। नोरसांग खाम प्रांत के पारंपरिक शग रोंगपो इलाके के गेसो सबा नामक गांव से ताल्लुक रखते थे। वह सोनम यांग और गंगचुंग के पुत्र थे। उनके परिवार में पिता, पत्नी और छह बच्चे हैं।

शग रोंगपो क्षेत्र पर कड़ी निगरानी और कड़े प्रतिबंध जारी हैं क्योंकि स्थानीय तिब्बतियों से लगातार पूछताछ की जा रही है जबकि संदिग्ध व्यक्तियों के सेलफोन जब्त किए जा रहे हैं और उनके घरों की तलाशी ली जाती है ताकि 'अलगाववाद' से लड़ने के नाम पर स्थानीय लोगों का निर्वासित लोगों के साथ किसी भी संभावित संबंध का पता लगाया जा सके।

— डीआईआईआर के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क द्वारा जारी •

भारत-तिब्बत सम्बन्ध संघ ने नया सिक्योंग निवाचित होने पर पेब्या ल्सेरिंग को बधाई दी

tibet.net, 28 मई, 2021

27 मई, 2021 : कुछ महीने पहले 'भारत-तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस)' नाम से स्वतंत्र रूप से गठित तिब्बत समर्थक समूह ने अपने सदस्यों के बीच एक आभासी बैठक आयोजित की और कुछ नई

नियुक्तियों की घोषणा की। यह बैठक बीटीएसएस संस्थापक सदस्य श्री सौरभ सारस्वत ने बुलाई और इसकी अध्यक्षता संघ के उपाध्यक्ष (सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल) श्री ओ.पी. तिवारी ने की।



भारत तिब्बत समन्वय संघ के वेबिनार में भाग लेते हुए।

सत्र के दौरान श्री सारस्वत ने संगठन के महत्व और उसके उद्देश्यों को निर्धारित किया। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश पीश और झारखण्ड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा को बीटीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने और पारित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगी। इसके बाद श्री नीलेंद्र कुमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) का परिचय दिया गया जो बीटीएसएस के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे।

दो ऐतिहासिक घटनाएं संयोग से एक ही दिन घटीं और आभासी सत्र में उपस्थित बीटीएसएस के सभी सदस्यों ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए सिक्योंग (अध्यक्ष) के रूप में चुने जाने पर पेंपा त्सेरिंग को हार्दिक बधाई दी। सभी सदस्यों ने तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों पर चीनी कम्युनिस्ट सरकार के अन्याय के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विश्वास को भी दोहराया।

श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा ने बौद्ध धर्म और सत्य के मूल्यों में अपनी आस्था पर जोर दिया, जिसका तिब्बती लोगों द्वारा उनके संघर्ष में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। वह उन दिनों को याद करती हैं जब उन्होंने झारखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजगीर की यात्रा की थी और उस दौरान तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कुछ करने के लिए उन्हें कैसे उत्साहित किया गया था। उन्होंने बीटीएसएस की अध्यक्ष का पदभार विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और अपनी सेवा के द्वारा इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में

चीन ने अभिभावकों से कहा-तिब्बती स्कूलों में कोई धर्म नहीं होगा छात्रों के माता-पिता अब धार्मिक वस्तुओं को स्कूल के मैदान में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि चीन तिब्बतियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने वाली नीतियों को लागू करता ही जा रहा है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र नागचु (नाकू) प्रान्त में सोग (चीनी: सूओ) काउंटी में रहने वाले एक तिब्बती ने आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि परिवार के सदस्यों को अब अपने बच्चों के स्कूलों में जाने पर मन्त्र या अन्य प्रार्थनाओं का पाठ करने की मनाही है।

rfa.org, 10 मई, 2021

एक तिब्बती काउंटी में चीनी अधिकारियों का कहना है कि तिब्बती काउंटी के बच्चों के माता-पिता अब माला, प्रार्थना-चक्र या अन्य धार्मिक वस्तुओं को स्कूल के मैदान में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि चीन तिब्बतियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने वाली नीतियों को लागू करता ही जा रहा है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र नागचु (नाकू) प्रान्त में सोग (चीनी: सूओ) काउंटी में रहने वाले एक तिब्बती ने आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि परिवार के सदस्यों को अब अपने बच्चों के स्कूलों में जाने पर मन्त्र या अन्य प्रार्थनाओं का पाठ करने की मनाही है।

संभव मदद करने के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया।

श्री नीलेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में थिनेले चोकी भूटिया से तिब्बती भाषा सीखने और सेना की बर्दी में राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के इन सभी वर्षों के अपने अनुभव को फिर से याद किया। उन्होंने उन पर विश्वास करने के लिए बीटीएसएस के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और आने वाले दिनों में वे निश्चित रूप से इसे हर संभव तरीके से भुनाने के प्रति विश्वास व्यक्त किया।

चार राष्ट्रीय सचिवों में से श्री रावल हरीश सेमवाल, गंगोत्री, उत्तराखण्ड य श्री माधवन, आंध्र प्रदेश और पूजनीय सुनील कौशल, वृद्धावन, उत्तर प्रदेश सत्र में शामिल हुए। अन्य उपस्थित लोगों में, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे मास मीडिया एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव भाई शर्माय उत्तराखण्ड के विधायक श्री पुष्कर सिंह धामीय भाजपा महिला मोर्चा की श्रीमती पूजा कपिल मिश्राय गुर्जर समुदाय के नेता श्री विजय भैंसलाय कवयित्री श्रीमती रुचि चतुर्वेदीय लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सेनानी श्री रिछापाल सिंह कवियाय हैदराबाद के श्री महेंद्र केसरीय विजयनगरम, आंध्र प्रदेश की श्रीमती शैलजाय नागपुर की श्री विजया केवल रमानीय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के डॉ. त्सुंडु डोलमाय स्पीति, हिमाचल प्रदेश की श्रीमती रिंगजिनय श्री उमाकांत स्वामी, श्री बावेश भाई, संजय तिवारी हिंदुस्तानी, न्यूज इंडिया, गुजरात के श्री. गौरव शर्मा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तिब्बती भाषा प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके श्री राम प्रताप चौधे उपस्थित थे। इसके अलावा, क्षेत्रीय संयोजक (बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़) श्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉर्ज- इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक (महाराष्ट्र और गोवा) श्री संदेश मेशमा ने भी सत्र में भाग लिया।

इन सभी सदस्यों के साथ ही आईटीसीओ के समन्वयक ने ने बारी-बारी से दो शब्दों में श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा और श्री नीलेंद्र कुमार को अपना-अपना कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी और उनका समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अंत में पूजनीय सुनील कौशल की अध्यक्षता में गायत्री मंत्र के जाप के साथ सत्र का समापन हुआ। सत्र दोपहर 3.00 बजे शुरू हुआ और शाम 4.30 बजे समाप्त हुआ।

— आईटीसीओ, नई दिल्ली द्वारा जारी ◆

आरएफए के सूत्र ने कहा, अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल सत्र के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए नए नियम छात्रों और उनके परिवारों को याद दिलाते हैं कि 'स्कूल कम्युनिस्ट विद्वानों को पैदा करने और उन्हें आगे बढ़ाने की जगह है और इसका उपयोग अनुच्छानों और परंपराओं का पालन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।'

आरएफए के सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'सोग काउंटी के सभी जूनियर और मिडिल स्कूलों में अब प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं और छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके



तिब्बती स्कूलों में जबरन पढ़ाए जा रही चीनी भाषा।

माता—पिता या अभिभावक को यह बता दिया जाना चाहिए कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए।'

सूत्र ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त श्रमिकों को पहले से ही धार्मिक रियाजों के पालन के खुले प्रदर्शन से मना किया गया है। लेकिन अब छात्रों के माता—पिता के व्यवहार पर लगाए गए ये नए प्रतिबंध उनके अधिकारों का सरासर उल्लंघन और तिब्बती धर्म और संस्कृति का अपमान हैं।

सूत्र ने कहा कि 'चूंकि चीन इस वर्ष (23 जुलाई) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कमर

कस रहा है, अधिकारी तिब्बती काउंटी, कस्बों, मठों और स्कूलों में पार्टी की विचारधारा को फैलाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'इन सभी स्थानों को सीसीपी के प्रति अपनी वफादारी सुनिश्चित करने के बारे में वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है।'

भाषा अधिकार पर लटकती तलवार

सूत्रों का कहना है कि तिब्बती स्कूलों में तिब्बती भाषा के इस्तेमाल पर पहले से ही प्रतिबंध है और मंदारिन में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बीच तिब्बती बच्चे अपनी भाषा का प्रवाह खोते जा रहे हैं।

हाल के वर्षों में तिब्बती राष्ट्रीय पहचान का दावा करने के मामले में भाषा अधिकार विशेष केंद्रबिंदु बन गया है। मठों और कस्बों में अना-पर्चारिक रूप से चलाए जा रहे भाषा पाठ्यक्रमों को अवैध घोषित किया गया है। इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिरासत में ले लिया जाता है या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है।

पूर्व में स्वतंत्र राष्ट्र रहे तिब्बत पर 70 साल पहले आक्रमण किया गया था और बल प्रयोग द्वारा इसे चीन में शामिल कर लिया गया था।

चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करते हुए उनका उत्पीड़न, यातना, कारावास और न्यायेतर हत्याएं जारी रखी हैं और इस क्षेत्र पर अपनी कड़ी पकड़ बनाए रखी हैं।

आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए ल्हुबूम द्वारा रिपोर्ट तैयार। तेनजिन डिकी द्वारा अनूदित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखित। ◆

सिक्योंग पेब्या त्सेरिंग ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की

tibet.net, 28 मई, 2021



सिक्योंग (राष्ट्रपति) श्री पेपा सेरिंग कोविड टास्क फॉर्म के साथ।

धर्मशाला। सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने प्रशासन में अपने पहले दिन गुरुवार को तेजी से कदम बढ़ाया और सीटीए कोविड-19 टास्क फॉर्म के साथ बैठक कर भारत और नेपाल में तिब्बती समुदायों में कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा की।

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि पद ग्रहण करने पर भारत और नेपाल में तिब्बती समुदायों में कोविड-19 महामारी से निपटना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा।

शुक्रवार को सिक्योंग ने धर्मशाला में तीन पृथक्वास केंद्रों का दौरा किया। इनमें नेलेनखांग का कोविड केयर सेंटर, अपर टीसीवी और मैक्लोडगंज का कोविड-केयर सेंटर शामिल हैं। इनका प्रबंधन सेटलमेंट ऑफिस और तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा अग्रिम मोर्चे पर तैनात कोरोना योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है।

बाद में उन्होंने डेलेक अस्पताल की नई एम्बुलेंस की उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इसकी पहली सवारी को झंडी दिखाकर

रवाना किया। गुरुवार तक भारत और नेपाल में तिब्बती समुदाय में कोरोना वायरस संक्रमण के 4385 नए मामले आए, 2942 मरीज ठीक हुए, 114 मौतें हुई और 1329 सक्रिय मामले दर्ज किए गए।

61वीं कोविड ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए डॉ त्सेरिंग त्सामचो ने इस सप्ताह 372 नए मामले दर्ज किए (210 पुरुष और 162 महिलाएं, जिसमें सबसे छोटा एक साल का बच्चा है और सबसे बड़ा 94 साल के बुजुर्ग हैं)। दुर्भाग्य से, इस सप्ताह मृत्यु दर बढ़कर 13 हो गई है।

टास्क फॉर्म की कोविड प्रतिक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने साप्ताहिक पृथक्वास केंद्र की स्थिति को अपडेट किया। वर्तमान में, 668 गृह पृथक्वास में हैं और 643 संस्थागत पृथक्वास में हैं। इस तरह कुल मिलाकर संख्या 1311 हो गई है।

इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने मेन-त्सी-खांग के साथ संयुक्त पहल में 35,798 इकाइयों के सोरिंग इम्यून बूस्टर का वितरण किया।

मानसिक स्वास्थ्य समिति ने इस सप्ताह 103 कोविड रोगियों को टेली-काउंसलिंग प्रदान की है।

इस सप्ताह भारत और नेपाल में बड़े पैमाने पर परीक्षण हुए और 2086 तिब्बतियों का परीक्षण किया गया।

टीकाकरण अभियान में 17,409 तिब्बतियों को टीका लगाया गया, जिनमें 1333 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, 1874 सह-रुग्नता वाले, 7790 बुजुर्ग 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले 5532 और 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले 880 तिब्बती शामिल हैं।

डॉ. त्साम्चो ने जनता से एहतियाती उपायों का पालन करते रहने की अपील की। उन्होंने जनता से टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने और डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों को ऐसा करने में मदद करने का भी आग्रह किया।

डॉ. तेनजिन त्सुंड्चू ने लोगों को बिना किसी डर या शंका के लक्षणों

की थोड़ी सी भी भनक मिलने पर परीक्षण कराने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट आती है तो उपरोक्त मानकों को अपनाने से तेजी से स्वस्थ होने की दर बढ़ेगी।

दिवंगत हुए तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों की याद में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने आभासी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया

tibet.net, 30 मई, 2021



भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि वेबिनार।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत में बहुत तबाही मचाई है। चीन के बुहान शहर से उत्पन्न हुआ कोविड-19 वायरस अभी भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। महामारी के कारण कई लोगों की अपनों और प्रियजनों की जान चली गई। इसी तरह, यह बहुत दुखद रहा कि हमने कुछ तिब्बत समर्थकों और तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान खो दिया। सभी दिवंगत आत्माओं की स्मृति में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने रविवार, 30 मई 2021 को वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चली इस सभा में दिवंगत श्री सुंदरलाल बहुगुणा, डॉ. दाऊजी गुप्ता, डॉ. पी.जी. ज्योतिकर, प्रो. भाऊ लोखंडे, श्री हरीश अड्यालकर, प्रो. विमलकृति, श्री नरेश माथुर, श्री जे.एम. मुखी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और स्वामी अग्निवेश को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा में भारत-तिब्बत मैत्री संघ के महासचिव डॉ. आनंद कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रारंभ में डॉ. आनंद

ताइवान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय निकायों के सांसदों ने 11वें पंचेन लामा को रिहा करने के लिए चीन पर दबाव डाला

tibet.net, 18 मई, 2021



केनेडा के सांसद आरिफ वीरानी पंचेन लामा का चित्र हाथ में लेते हुए।

उन्होंने सलाह दी कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं, उन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार, तीन महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद टीके का पहला डोज लेना चाहिए। •

कुमार ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने आभासी कार्यक्रम के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की। दिवंगत आत्माओं को याद करते हुए डॉ. आनंद कुमार ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में उनके सहयोग और योगदान को साझा किया।

भारत-तिब्बत मैत्री संघ के आयोजन सचिव डॉ. मनोज कुमार ने विशेष रूप से दिवंगत आत्माओं के बारे में विस्तार से परिचय दिया और उनके लिए प्रार्थना की और सम्मान दिया। इसी तरह कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों में से श्री सचिन रामटेक, श्री बृजेश कुमार, श्रीमती उमा घोष, रेशम बाला और श्री संदीप ज्योतिकर सहित अन्य सभी ने दिवंगत आत्माओं को एक-एक कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ)-दिल्ली के समन्वयक श्री जिम्मे त्सुलिंग ने दिवंगत तिब्बत समर्थकों के लिए अपनी गहरी प्रार्थना और सम्मान की पेशकश करते हुए कुछ दिवंगत आत्माओं से उनके जीवनकाल में मिलने के अपने अनुभव को याद किया और बताया कि उनसे मिलकर वह कितना धन्य महसूस कर रहे थे। दिवंगत आत्माओं का अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान था और उससे भी बड़ा योगदान तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देना था।

श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित सदस्यों ने भारत-तिब्बत मैत्री संघ की अब तक की यात्रा और दिवंगत सदस्यों द्वारा छोड़ी गई विरासत को याद करते हुए तिब्बत मुक्ति साधना के प्रति आगे की जिम्मेदारी के बारे में भी चर्चा की।

आभासी श्रद्धांजलि सभा में भारत-तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य, तिब्बत समर्थक और आईटीसीओ के कर्मचारी शामिल हुए। •

धर्मशाला। आज से ठीक 26 साल पहले 17 मई को एक छह वर्षीय लड़का अनजाने में लोगों की नजरों से ओझल हो गया। इस लड़के को परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा आधिकारिक तौर पर तिब्बत के 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मान्यता मिलने के तीन दिन बाद ही चीनी अधिकारियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद गेधुन चोएक्यी चियमा नामक इस लड़के के ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका है, जो दलाई लामाओं की वंशावली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उन्हें और उनके परिवार को रिहा करने के लिए दुनिया भर से चीन से बार-बार अपील की गई और उस पर दबाव डाला गया लेकिन फिर भी उनके बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि, चीनी सरकार ने बार-बार कहा है कि गेधुन चोएक्यी चियमा 'बहुत अच्छा जीवन' जी रहे हैं और अच्छा

कर रहे हैं, लेकिन इन वर्षों में अपने दावे को सत्यापित करने के लिए उसने एक भी सबूत पेश नहीं किए हैं।

गेधुन चोएक्यी न्यिमा के गायब होने के इन वर्षों में दुनिया भर के तिब्बतियों, बौद्धों और तिब्बत समर्थकों ने इस उम्मीद में उनकी अनुप्रिथ्वी में उनका जन्मदिन मनाया कि वह और उनका परिवार स्वरथ और सकुशल हैं और एक दिन, दुनिया उन्हें मुक्त देखेगी और तिब्बती लोग व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।

पंचेन लामा और उनके परिवार की तत्काल रिहाई की अपील अभी भी की जा रही है और हर बार अधिकार समूह, सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय अधिकार संगठनों द्वारा दुनिया भर में अधिक जोरदार और तेज ढंग से यह मांग उठाई जा रही है। उन्होंने गेधुन चोएक्यी न्यिमा और उनके परिवार की कुशलता के लिए लगातार चिंता व्यक्त की है और चीन से उन्हें और अन्य कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया है।

टॉम लैंटोस मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को चीनी सरकार से 'पंचेन लामा और उनके परिवार को बिना किसी शर्त के रिहा करने' का आह्वान किया।

गेधुन चोएक्यी न्यिमा के जबरन गायब होने की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ)' ने चीनी सरकार से 11वें पंचेन लामा के ठिकाने का खुलासा करने का आह्वान किया।

यूएससीआईआरएफ की आयुक्त नादिन मेंजा ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को गेधुन चोएक्यी न्यिमा के स्वास्थ्य की जांच करने की अनुमति देने पर जोर दिया।

यूएससीआईआरएफ ने मेंजा के बयान को ट्रीट करते हुए लिखा, 'दलाइलामा ने 14 मई, 1995 को गेधुन चोएक्यी न्यिमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी। हम चीनी सरकार से गेधुन के ठिकाने के बारे में जानकारी देने और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को उनकी कुशलता की पुष्टि करने के लिए उनसे मिलने की अनुमति देने की अपनी मांग को दोहराते हैं।'

पिछले महीने गेधुन चोएक्यी न्यिमा के 32वें जन्मदिन के अवसर पर यूएससीआईआरएफ ने उनको रिहा करने के लिए चीनी सरकार से अपना आह्वान दोहराया था।

यूएससीआईआरएफ की उपाध्यक्ष नादिन मेंजा ने कहा, 'चीनी सरकार तिब्बती बौद्ध धर्म को दबाने के लिए इतनी बेताब है कि उसने छह साल के लड़के का अपहरण कर लिया।' उन्होंने आगे कहा, 'दुर्भाग्य से, गेधुन की दुखद दुर्दशा लाखों चीनी अनुयायियों के संघर्ष का प्रतिनिधि त्वर करती है, जो अपने विश्वास की साधना करने में अभूतपूर्व कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।'

इसी तरह, तिब्बत के 11वें पंचेन लामा की कुशलता के लिए चिंता व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सांसद जेनेट राइस ने गेधुन चोएक्यी

स्विस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, यूके, बाल्टिक देशों, यूरोपीय संघ, चिली और टीएसजी के सांसदों ने सिक्योंग पेब्या ल्यैरिंग को बधाई दी

tibet.net, 28 मई, 2021

धर्मशाला। परम पावन दलाइलामा द्वारा राजनीतिक भूमिका के पूर्ण हस्तांतरण के बाद से निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के तीसरे लोकतांत्रिक चुनाव में रेतिहासिक और अभूतपूर्व जीत दर्ज कराने के बाद दुनिया भर के नेताओं ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नव निर्वाचित सिक्योंग श्री पेन्चा त्सेरिंग को बधाई दी है।

स्विस, कनाडा, ब्रिटेन, बाल्टिक राज्यों, यूरोपीय संघ, चिली, जर्मनी और नॉर्वे में तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों, सांसदों और दुनिया भर

न्यिमा के ठिकाने को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने ट्रीट किया, 'चीनी सरकार को तिब्बती भिस्तुओं और लामाओं द्वारा पंचेन लामा के रूप में पहचाने जाने वाले बच्चे को हिरासत में लिए हुए 26 साल हो चुके हैं। चीनी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस समय किस रिथ्विति में और कहां हैं? साथ ही स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को उन तक पूर्ण पहुंच प्रदान करनी चाहिए।'

तिब्बत मुद्रे के प्रबल समर्थक फ्रेडी लिम ने हैशटैग फ्री पंचेन लामा का उपयोग करते हुए गेधुन चोएक्यी न्यिमा की तत्काल रिहाई की अपील की।

उन्होंने कल फ्री पंचेन लामा हैशटैग से ट्रीट किया 'महामारी से लड़ने के साथ ही हम अभी भी मानवाधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। 26 साल पहले, सीसीपी द्वारा पंचेन लामा को हिरासत में लिया गया था, तब वह सिर्फ 6 साल के थे। चीन अभी भी उसे रिहा करने से इनकार करता है, या उनके और उनके परिवार के बारे में किसी भी वास्तविक जानकारी का खुलासा नहीं करता है।'

तिब्बत के 11वें पंचेन लामा की तत्काल रिहाई के आह्वान में शामिल होते हुए, सांसद आरिफ विरानी ने 11वें पंचेन लामा की बिना शर्त रिहाई के अभियान में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, '2018 में ओटावा में विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय विकास पर स्थायी समिति के सामने पेश हुए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के तिब्बती प्रतिनिधिमंडल से सीधे पंचेन लामा के ठिकाने के बारे में पूछने का अवसर मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया था कि वह ठीक हैं और परेशान नहीं होना चाहते। मैं पंचेन लामा की वक्त लात करना जारी रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि एक दिन हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने लोगों के बीच देखेंगे।' इसी तरह, कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद कैथे वागंटाल ने इस अवसर पर अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी सरकार द्वारा गेधुन चोएक्यी न्यिमा का अपहरण मुख्य रूप से 'धार्मिक विश्वास और अभिव्यक्ति को दबाने' के लिए किया गया है।

सांसद वागंटाल ने फेसबुक पर लिखा, 'मैं पंचेन लामा की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के आह्वान में शामिल होता हूं। इसी तरह गेधुन के अपहरण की 26वीं वर्षगांठ पर कनाडा को भी अपील जारी करना चाहिए।'

ऑस्ट्रेलियाई सांसद सुसान टेम्पलमैन ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि पंचेन लामा की रिहाई के लिए अभियान का हिस्सा बनने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था और आगे उन्होंने 'सांसद की अगली बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया में दलाइलामा के कार्यालय के नए प्रतिनिधि श्री कर्मा सिंगे से मिलने की इच्छा व्यक्त की।' •

के तिब्बत समर्थक दोस्तों ने नव निर्वाचित नेतृत्व को पत्र लिखकर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और सीटीए और तिब्बती मुद्रे के प्रति नए सिरे से समर्थन व्यक्त किया।

इटली-तिब्बत अंतर संसदीय समूह के अध्यक्ष माननीय लुसियानो नोबिली ने लिखा, 'दलाइलामा के नेतृत्व में तिब्बती जिस लोकतांत्रिक संगठन को निर्वासन में स्थापित करना चाहते थे, वह हमारे समर्थन के मुख्य कारणों में से एक है। आपका एक समाज, होता है जो दूसरे देश

में अत्यधिक कठिनाई के बावजूद नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना चाहता है, वह सबसे पहले अपनी संस्कृति के सबसे प्रतिनिधित्व तत्वों के संरक्षण के बारे में, अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, सार्वजनिक मामलों के लोकतांत्रिक प्रबंधन के संदर्भ में सोचना चाहता है।

इटली-तिब्बत अंतर संसदीय समूह में अब संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के 54 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता कर मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस समूह को पहले से ही इतालवी संस्थानों के भीतर तिब्बत मुद्दे से संबंधित विभिन्न पहलों को आयोजित करने का अवसर मिला है। इसमें से अंतिम, इस वर्ष 10 मार्च को आपके पूर्ववर्ती डॉ. लोबसांग सांगेय की उपस्थिति में टेली कांफेंस थी।

लातविया औचे की संसद में तिब्बत समर्थन समूह के अध्यक्ष सांसद श्री उल्दिस बुद्रिकीस, लिथुआनियाई संसद में तिब्बतियों के साथ एकजुटता के लिए अनन्तिम समूह के अध्यक्ष सांसद श्री अंद्रिअस नाविकस, एस्टोनिया संसद में तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष सांसद योकोज अलेंडर ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष सिक्योंग पेन्या त्सेरिंग को बधाई पत्र भेजा और तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की।

उन्होंने लिखा, 'हमें विश्वास है कि आप अपने लोगों को वह स्वतंत्रता दिलाने में सफल होंगे जिसकी वे आकांक्षा रखते हैं। हम बाल्टिक देश आपके साथ खड़े रहेंगे और आप हमेशा हमारे समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। हम आपके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देते हैं और तिब्बती लोगों की भलाई के लिए अपनी ओर से समर्थन देने की पेशकश करते हैं।'

यूरोपीय संघ की संसद में तिब्बत हित समूह के सदस्य और यूरोपीय संघ के सदस्य मिक्रलास पेक्सा, यूरोपीय संसद में तिब्बत हित समूह के अध्यक्ष, ऑउरा मालदेझिकिएना (एमईपी, ईपीपी), हेंस हीड (एमईपी, एसएंडडी), कार्ल्स पुझगडेमॉट आई कैसामाजो (एमईपी, एनआई), एंटोनी कॉमिन और ओलिवर्स (एमईपी, एनआई), क्लारा पोन्साती ओविआ. 'ल्स (एमईपी, एनआई), इवान स्टेफेनेक (एमईपी, ईपीपी), पैट्रिक ब्रेयर (एमईपी, ग्रीन्स्वर्डएफए) और माइकल गहलर (एमईपी, ईपीपी) ने निर्वासित तिब्बती संसद के लोकतांत्रिक चुनाव के सफल संचालन की सराहना की तथा नए सिक्योंग और संसद सदस्यों को बधाई दी।

उन्होंने लिखा, 'हम इस अवसर का उपयोग आपको ब्रसेल्स में आमंत्रित करने के लिए करना चाहते हैं—जैसे ही स्थिति इसकी अनुमति देती है—तिब्बत की स्थिति के बारे में हमारे साथ आदान-प्रदान करने के लिए और उन तरीकों के बारे में बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनसे यूरोपीय संसद तिब्बती लोगों के मानवाधिकार की स्थिति में सुधार करने में योगदान दे सकती है।'

उन्होंने लिखा, हम सीटीए और चीनी सरकार के बीच मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के अनुरूप सीधी बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से तिब्बत संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं और इसके लिए आपके साथ काम करने को तत्पर हैं।

नए सिक्योंग को बधाई पत्रों की सूची में शामिल होते हुए हंगरी के बुडापेस्ट के बुडावर (प्रथम जिला) के उप महापौर श्री फेरेंक गेलेंसर ने अपनी शुभकामनाएं दीं और तिब्बत मुद्दे के महत्व के बारे में अवगत कराया।

'मैं तिब्बत के लोगों की करुणा और प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा करना चाहूंगा, जो अपने राष्ट्र को एक बार फिर से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'सदियों तक विदेशी शासन के अधीन रहे देश हंगरी का एक नागरिक होने के तौर पर मैं आप लोगों के संघर्ष को समझता हूं। हमारे समय की चुनौतियाँ हम सभी को याद दिलाती हैं कि क्यों लोकतंत्र एक आवश्यकता है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते।'

इसी तरह, ब्रिटिश संसद में तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजीटी) के सदस्यों की ओर से एपीपीजीटी के अध्यक्ष सांसद टिम लॉटन ने 'तिब्बत मुद्दे को साझा और समर्थन करने वाली मित्रता को निरंतर बनाए रखने और इस बीच तिब्बत में अत्याचार को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की।'

सांसद लॉटन ने और आगे लिखा कि 'एपीपीजीटी अधिकारियों और सदस्यों के साथ ही मैं आपके साथ भी मिलकर काम करने और तिब्बत और उसके लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए चीन की सरकार को चुनौती देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए तत्पर हूं।' उन्होंने आगे जोड़ा कि जब कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार होगा तो वह नए सिक्योंग की ब्रिटेन यात्रा का इंतजार करेंगे।

एपीपीजीटी के सदस्यों में इसके सह अध्यक्ष और सांसद क्रिस लॉ, लिवरपूल के लॉर्ड एल्टन, सांसद सर पीटर बॉटमली, सांसद मैरियन फेलो, सांसद वेरा हॉबहाउस, सांसद केरी मैकार्थी और सांसद नवेंदु मिश्रा शामिल हैं।

चिली गणराज्य के एरिका और परिनाकोटा से संसद सदस्य मान नीय व्लाडो मिरोसेविक वेरगुडो ने नवनिर्वाचित सिक्योंग को बधाई संदेश भेजा।

उन्होंने लिखा, 'हार्दिक अभिवादन के साथ मैं आपको चुनावी जीत के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इस चुनाव में जीत कर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति बने हैं और आपको निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया है।'

सांसद ने टिप्पणी की, 'आपने तिब्बती मुद्दे को हल करने, निर्वासित तिब्बतियों की कुशलता की देखभाल करने और चीन के साथ बात चीत के सभी संभावित रूपों को बढ़ावा देने की बात की है, और यही कारण है कि चिली के लोग तिब्बती लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द—सिक्योंग—के रूप में सफलता पाने में आपके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने में एकजुट हैं।'

कनाडा में पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत (पीएफटी) के अध्यक्ष सांसद आरिफ विरानी ने लिखा: 'ताशी डेलेक और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग (राष्ट्रपति) चुने जाने पर पेन्या त्सेरिंग ला को बधाई और निर्वर्तमान सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगेय को 10 साल की सेवा के लिए धन्यवाद।'

उन्होंने लिखा, 'मैं ओटावा में सिक्योंग पेन्या त्सेरिंग ला का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं और उनके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूं और तिब्बती लोगों के लिए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक स्वतंत्रता की बकालत करता हूं।'

कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह के उपाध्यक्ष, सांसद गार्नेट जेनुइस ने ट्रिवटर पर सिक्योंग—निर्वाचित त्सेरिंग और निर्वर्तमान सिक्योंग डॉ. सांगेय—दोनों को बधाई दी, क्योंकि उन्होंने 'लोकतांत्रिक संस्था निर्माण के लिए तिब्बती लोगों की प्रतिबद्धता' को आगे बढ़ाया।

जर्मन बुंडेस्टाग के सदस्य माइकल ब्रांड ने नए सिक्योंग को बधाई देते हुए लिखा कि निर्वासित तिब्बतियों जैसी लोकतांत्रिक सरकार ने विश्व सरकारों, विशेषकर बीजिंग में चीनी सरकार के लिए एक मिसाल कायम की है कि जबरदस्ती और आतंक का शासन, शासन का सही तरीका नहीं है। बल्कि लोगों के शासन की जीत होती है।

उन्होंने कहा, 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत भविष्य में तिब्बती लोगों, उनकी संस्कृति और उनके लोकतांत्रिक नेतृत्व का साथ देने और उनका समर्थन करने के लिए और अधिक इच्छुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैसे परम पावन ने उन्हें तिब्बती सरकार का समर्थन करने और उनकी दोस्ती को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से प्रेरित किया।

उन्होंने लिखा, 'इसलिए मुझे इस अनुकरणीय और विशिष्ट लोगों के हित में और उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए जर्मनी और यूरोप के साथ—साथ पूरी दुनिया में तिब्बत के दोस्तों के साथ मिलकर और नई तिब्बती सरकार के साथ मिलकर काम करने में प्रसन्नता हो रही है।'

यह बहुत खुशी की बात है कि हम आपको केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देते हैं।

हम निर्वासन में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना के लिए दलाई लामा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना और स्वागत करते हैं और तिब्बती निर्वासित समुदाय को एक बार फिर से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देते हैं।

नॉर्वेजियन सांसद पेटर ईड (सोशलिस्ट लेपट पार्टी) यूरोप की परिषद की संसदीय सभा के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और ऊर्जा और पर्यावरण पर राज्यायी समिति के अध्यक्ष सांसद केटिल केजेन्सथ (लिबरल पार्टी) अध्यक्ष ने भी बधाई संदेश भेजा।

उन्होंने लिखा, 'यह बहुत खुशी की बात है कि हम आपको केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में आपके चुनाव पर हार्दिक बधाई देते हैं। हम निर्वासन में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना के लिए दलाई लामा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना और स्वागत करते हैं, और तिब्बती निर्वासित समुदाय को एक बार फिर से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने का संदेश देते हैं।'

इस बीच, लातविया (बाल्टिक देशों) में तिब्बत के मित्रों और समर्थकों ने अपने देशों में नए सिक्योंग की संभावित यात्रा कराने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने नए सिक्योंग पेन्चा त्सेरिंग को बधाई देते हुए लिखा, 'बहुत काम है और हम तिब्बत के मित्र, भाई और बहन, विचार, हृदय और कार्यों में तिब्बत के साथ हैं और रहेंगे।'

मेकिस्को में एक प्रमुख तिब्बत समर्थक समूह—तिब्बत एमएक्स ने श्री त्सेरिंग को भेजे अपने बधाई—पत्र में परम पावन दलाई लामा और

भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि अब्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ सीमा पर तनाव जारी नहीं रह सकता: तिब्बत नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता

tibet.net, 24 मई, 2021

पैंगोंग त्सो के अलावा तनाव के अन्य बिंदुओं पर से सैनिकों की वापसी की धीमी प्रगति के साथ—साथ कायम गतिरोध को लेकर भारत की नाराजगी साफ झलकती है। तनाव वाले शेष बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने में कोई गति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि '9 अप्रैल को भारतीय सेना के साथ सैन्य वार्ता के 11 वें दौर में चीनी पक्ष ने अपने रुख में कोई लचीलापन नहीं दिखाया।

चिंताजनक खबरें यह भी हैं कि चीन ने प्रशिक्षण क्षेत्रों में और सैनिकों को तैनात किया है। चीन की दीर्घकालिक योजनाएं स्पष्ट रूप से दक्षिण चीन सागर (एससीएस) के अपने पूर्व के प्रयोगों को दोहराने की हैं, जिसके तहत जमीनी तथ्यों को बदलकर अपने पक्ष में करने का इरादा साफ दिखता है।

सीटीए द्वारा निर्देशित तिब्बती लोगों के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध होने की फिर से पुष्टि की।

'तिब्बत एमएक्स वैध तिब्बती अधिकारियों और मेकिस्को के लोगों के बीच सेतु है और रहेगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और स्थिति की अनुमति मिलते ही आपसे और आपके प्रतिनिधियों से मिलने की उमीद करते हैं।'

27 मई को लिखे अपने बधाई संदेश में तिब्बत के लिए स्विस—संसदीय समूह के सह—अध्यक्षों और उपाध्यक्ष ने तिब्बत मुद्दे पर अपने निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता को फिर से व्यक्त किया।

जब भी संभव हो, हम तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर पहल के साथ संसद में सक्रिय हो जाते हैं और हम इस बात पर जोर देते हैं कि स्विस सरकार हमेशा चीनी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अपने संपर्क के माध्यम से तिब्बती लोगों के अधिकारों के वकालत करे। तिब्बती गैर सरकारी संगठनों और जिनेवा में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ निकट संपर्क का लाभ उठाते हुए हम तिब्बती चिंताओं को स्विस राजनीति में लाने के तरीकों की तलाश करते हैं।'

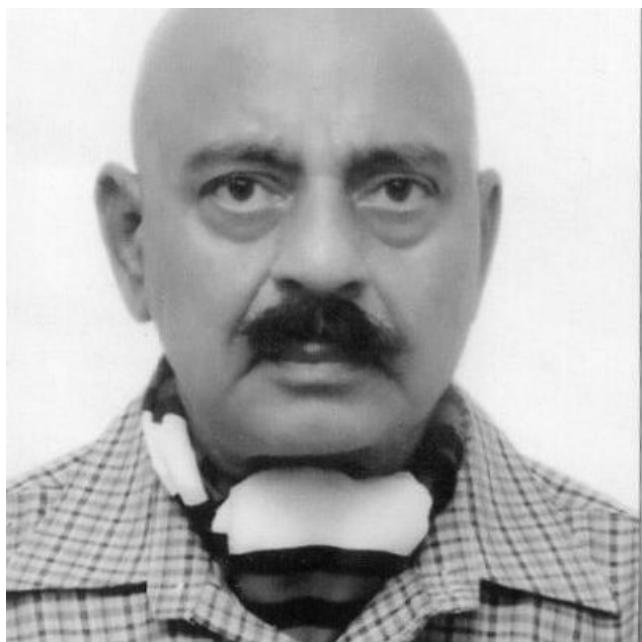
इस उद्देश्य के लिए उन्होंने भविष्य में नए सीटीए नेतृत्व के साथ इस 'मूल्यवान सहयोग' को जारी रखने की आशा की और निर्वासित तिब्बती संसद में नव निर्वाचित संसदीय सहयोगियों को एक सफल विधायिका के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इतिहास तिब्बत के लिए एक सकारात्मक मोड़ ले सकता है। पत्र सह अध्यक्ष सांसद निक गुगर, सह अध्यक्ष सांसद फैबियन मॉलिना, सह—अध्यक्ष सांसद निकोलस वाल्डर और उपाध्यक्ष सांसद माया ग्राफ के हस्ताक्षर से जारी किया गया।

इसी तरह, स्विस—तिब्बतन फ्रेंड्सिप एसोसिएशन ने नए शपथ ग्रहण करने वाले सिक्योंग श्री पेन्चा त्सेरिंग को बधाई दी।

एसटीएफए के अध्यक्ष थॉमस बुचली और एसटीएफए के उपाध्यक्ष ल्हांग नागोरखांगसर ने लिखा, 'हम आपको और तिब्बती संसद में नव निर्वाचित चिंतुओं के लिए सफल विधायिका की कामना करते हैं।'

उन्होंने आगे लिखा, 'आपके पूर्ववर्ती सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगेय के साथ विभिन्न बैठकों में हमें धर्मशाला में निर्वासित सरकार से प्रत्यक्ष और मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई। हम आपके साथ इस आदान—प्रदान को जारी रखना चाहेंगे। हम निकट भविष्य में सिक्योंग के रूप में आपके साथ सीधे संपर्क बनाए रखने के लिए आपकी स्विट्जरलैंड यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।'

चीनी कार्बाइड्स के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन जान—बूझकर अन्य स्थानों पर सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में देशी कर रहा है। चीनी गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स के पास विवादित क्षेत्रों में भारत की गश्त को रोक रहा है। ये दोनों स्पॉट पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के गालवान सब—सेक्टर में चांग चेनमो नदी के करीब हैं। जबकि हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो नदी के उत्तर में हैं। गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां नदी गलवान घाटी से दक्षिण—पूर्व में आने और दक्षिण—पश्चिम की ओर मुड़ते हुए एक हेयरपिन मोड़ लेती है। चीन की योजना स्पष्ट रूप से इस स्थिति को धीरे—धीरे स्थिर करने की है। भारतीय सेना जहां पहले गश्त कर रही थी, वहां उसे गश्त से रोकना चीन के लिए लाभ की स्थिति है।



एस.डी. प्रधान

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक आयाम पर स्पष्टता के साथ टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 'संबंध एक चौराहे पर है और हम किस दिशा में जाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीनी पक्ष दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन करेगा या नहीं।'

उन्होंने आगे कहा कि 'अन्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ सीमा पर तनाव जारी नहीं रह सकता है।' उन्होंने यह भी बताया कि अगर रक्तपात के साथ सीमा पर शांति भंग होती है तो इस तरह के कृत्य निश्चित रूप से संबंधों को प्रभावित करने वाले हैं। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि जब एक तरफ से रिश्ते का उल्लंघन किया गया हो तो उसे संभालना मुश्किल होता है।

कटू सत्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन अपने चारों ओर के सीमाई क्षेत्रों में अधिक से अधिक आक्रामक हो गया है। चीन ने अपने दावे पर जोर देने के लिए जमीनी हकीकत में एकतरफा बदलाव किया है। इसने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया और उन्हें दक्षिण चीन सागर में हथियार बनाया। पूर्वी चीन सागर में वायु रक्षा पहचान क्षेत्र की स्थापना की और पूर्वी लद्धाख में क्षेत्रों को हथियाने की कोशिश की।

चीनी आबादी को अति-राष्ट्रवाद और सुविधावादी विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाती है। हाई वोल्टेज झूठे प्रचार में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके चारों ओर के क्षेत्र चीन के थे, जो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों से हार गए थे। ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है और यहां तक कि उनके तर्कों को प्रमाणित करने के लिए गलत तथ्यों को गढ़ा जाता है।

चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में भारत की वर्षों की हिचकि-चाहट से चीन की यह धारणा मजबूत हुई है कि भारत उसकी प्रगति का विरोध नहीं करेगा। कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि भारत ने चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई है।

उधर, चीन रक्षा और परमाणु क्षेत्रों में पाकिस्तान का समर्थन करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में पाक आतंकवादियों को समर्थन प्रदान करता है, आक्रामक रूप से पूरे अरुणाचल प्रदेश की मांग करता रहता है, हिंद महासागर में भारत के चारों ओर ठिकाने बनाता है, जिसका भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे और निहितार्थ है और एनएसजी में भारत के

प्रवेश का विरोध करता है। दूसरी ओर भारत सीमा पर शांति स्थापना को लेकर ही संतोष दिखा रहा था और मानता था कि सीमा समझौता उसके सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त थे। बावजूद इसके कि चीन चुपके से क्षेत्रों को हथियाने का प्रयास कर रहा था जैसा कि 2013 की देपसांग की घटना से स्पष्ट भी हो गया था।

यह पाकिस्तान और नेपाल को भी भारत के खिलाफ नकशानवीसी की आक्रामकता में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने की वर्षगांठ पर एक नया नक्शा प्रदर्शित किया, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की सीमा चीन के साथ लगती है।

20 मई 2020 को नेपाल सरकार ने भारत के उत्तराखण्ड राज्य के पूर्वी कोने में मौजूद कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाते हुए अपना खुद का नक्शा लॉन्च किया। इससे भी अधिक चिंताजनक और उत्तेजक कदम भूटान के क्षेत्रों पर कब्जा करना है। मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चीन ने भूटान के अंदर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक पूरा शहर, सड़कों का जाल, एक बिजली संयंत्र, दो सीपीसी भवन, सैन्य और पुलिस चौकियों के साथ एक संचार बेस बना लिया है। भूटान में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डालते हुए ट्राइजंक्शन को दक्षिण की ओर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बड़ी तस्वीर से पता चलता है कि हमारी सीमा समस्याएं चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के कारण उत्पन्न हुई हैं। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अथव प्रयास कर रहा है। वस्तुस्थिति इस आयाम को मान्यता देने की मांग करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत बताता है कि तिब्बत को वास्तविक स्वशासन मिले। हालिया घटनाक्रम इसके पक्ष में हैं।

इसलिए, हमारी तिब्बत नीति की समीक्षा महत्वपूर्ण है।

निर्वासित तिब्बती दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर निर्णय लेने के चीनी प्रयासों और तिब्बतियों के उत्पीड़न को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हो रहे हैं। उनमें से एक वर्ग अब चीन से स्वतंत्रता की मांग करता है जैसा कि निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व राष्ट्रपति लोबसांग सांगेय के बयान से स्पष्ट है कि तिब्बती ध्वज ल्हासा में पोटाला पैलेस के ऊपर फहराएगा और दलाई लामा मुक्त होकर वहां विचरण करेंगे।

तिब्बत पर अपने कब्जे के बाद से ही चीन दमनकारी नीतियों का अनुसरण कर रहा है, जिससे वहां के निवासियों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। अगस्त 2020 में तिब्बत पर सातवीं केंद्रीय संगोष्ठी में लिए गए निर्णय का उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और धर्म को नष्ट करना और असंतोष को बड़े पैमाने पर कुचलना था। शी ने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला, बौद्ध संस्कृति का चीनीकरण दूसरा, सीसीपी की राजनीतिक और वैचारिक शिक्षा को तिब्बती स्कूलों में पुनर्जिक्षा शिविरों के माध्यम से लागू करना और तीसरा, तिब्बत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तिब्बतियों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। तिब्बतियों पर व्यापक हाई-टेक निगरानी रखी जाती है। इस कारण अतीत में कई तिब्बतियों ने यातना और दमन के कारण आत्महत्या कर ली है।

हालाँकि, चीन ने 21 मई 2021 को एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें भारत, भूटान और नेपाल के साथ तिब्बत की सीमा पर स्थित दूरदराज के गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के उसके प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। '1951 से तिब्बत: मुक्ति, विकास और समृद्धि'

शीर्षक वाले दस्तावेज ने तिब्बत के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। हालांकि, यह सच्चाई से कोसों दूर है। बेशक, वे सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं लेकिन अपने आगे के विस्तार के लिए, न कि तिब्बतियों की मदद करने के लिए।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने तिब्बत मुद्रे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है। अमेरिकी दृष्टिकोण अब मानवाधिकारों के उल्लंघन और तिब्बतियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने—दोनों को ध्यान में रखता है। तिब्बतियों की मदद के लिए अमेरिका में तिब्बतन पॉलिसी एंड सोर्ट ऐक्ट-2020 को मंजूरी दी गई है। यह अधिनियम अमेरिकी नीति को आधिकारिक बनाता है कि दलाई लामा, विशेष रूप से वर्तमान दलाई लामा के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी तिब्बती बौद्ध नेताओं और तिब्बती लोगों को मानता है। साथ ही इस कानून के तहत अमेरिका ल्हासा में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) को

दुनिया भर में तिब्बती आकांक्षाओं को प्रतिविवित करने वाली वैध संरथा मानता है। अमेरिका ने तिब्बत के लिए विशेष समन्वयक भी नियुक्त किया है, जो तिब्बतियों के राजनीतिक अधिकारों और संप्रभुता को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत को तिब्बतियों के धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ अपने दृष्टिकोण को समन्वित करने की आवश्यकता है। भारत 2003 के समझौते से बाध्य नहीं है क्योंकि यह इस समझ पर आधारित था कि 'कोई भी पक्ष दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा या धमकी नहीं देगा।' पूर्वी लदाख में बल प्रयोग कर एकतरफा कार्रवाई करते हुए चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया है और वह समझौता अब निरस्त हो गया है। अब भारत को तुरंत अपनी तिब्बत नीति की समीक्षा करनी चाहिए। इस दिशा में तिब्बतन पॉलिसी एंड सोर्ट ऐक्ट एक नजीर बन सकता है और भारत उसका अपना संस्करण तैयार कर सकता है। साथ ही तिब्बतियों की समस्याओं के सीधे संपर्क में रहने के लिए एक समन्वयक नियुक्त कर सकता है। ◆

तिब्बत के साथ चीन के 17-सूत्रीय समझौते के कारण बीजिंग ने किया तिब्बत का उत्पीड़न: विशेषज्ञ समझौते को चीन द्वारा तिब्बत पर थोपा गया था। इस दौरान तिब्बती वाताकारों द्वारा बीजिंग की मांगों को नहीं मानने पर चौतरफा युद्ध की धमकी दी गई थी।

rfa.org, 25 मई, 2021



रिचर्ड फिनरेन

चीन और तिब्बत के बीच एक 17-सूत्रीय विवादास्पद समझौता 1951 में हुआ था, जिसके आधार पर बीजिंग ने स्वतंत्र हिमालयी देश पर कब्जा कर लिया था। इस समझौते पर तिब्बत से दबाव डालकर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे और चीन द्वारा तुरंत बाद इसकी शर्तों का उल्लंघन कर लिया गया था। अधिकार समूहों और विशेषज्ञों ने समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर की 70 वीं वर्षगांठ पर उक्त विचार व्यक्त किए।

दस्तावेज पर 23 मई, 1951 को हस्ताक्षर किए जाने की 70वीं

वर्षगांठ से दो दिन पहले 21 मई को जारी एक सरकारी श्वेत पत्र में चीन ने कहा कि समझौते ने तिब्बत को 'चीन के अन्य जातीय समूह के साथ एकता, प्रगति और विकास की उज्ज्वल सड़क पर आगे बढ़ने के लिए मुक्त कर दिया था।'

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में तिब्बती भाषा के व्याख्याता चुंग त्सेरिंग ने एक साक्षात्कार में आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि हालांकि, समझौते में इस्तेमाल की गई भाषा स्पष्ट करती है कि तिब्बत के पास अपनी सरकार, सेना, संस्कृति और परंपराओं के साथ एक स्वस्वासी क्षेत्र था।

त्सेरिंग ने कहा, 'चीन में 55 अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों में से तिब्बत एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसके साथ चीनी सरकार ने ऐसा समझौता किया है। इसलिए हमें यह विचार करना होगा कि यह तिब्बत को अद्वितीय और विशिष्ट बनाता है।'

त्सेरिंग ने कहा, 'यदि हम 17-सूत्रीय समझौते को विस्तार से देखें तो कोई भी देख सकता है कि तिब्बत में अपनी सरकार, राजनीतिक और धार्मिक नेता, विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, सैन्य और भाषा के साथ संपूर्ण देश की विशेषताएं हैं।'

उन्होंने कहा, 'और अब, जब कोई 70 साल बाद भी इस समझौते को देखता है, तो ये तथ्य और भी स्पष्ट होते हैं।'

विशेषज्ञ कहते हैं कि समझौते को चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन थोपा गया था। चीन ने देश के पूर्वी हिस्से में तिब्बती सेना को हराया था और यदि तिब्बती सरकार द्वारा बीजिंग में बातचीत करने के लिए भेजा गया प्रतिनिधिमंडल चीनी मांगों के आगे नहीं झुकता तो वह बाकी तिब्बत में पूर्ण पैमाने पर युद्ध की धमकी दे रहा था।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रा. 'फेसर जिम्मे येशे कहते हैं, 'और बाद में चीन ने समझौते में उल्लिखित

तिब्बत की सरकार के कामकाज या तिब्बत के शासक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की स्थिति और भूमिका में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिज्ञा का उल्लंघन तो किया हो, अपने हिस्से का भी सम्मान नहीं किया।'

येशे ने कहा, 'उन्होंने तिब्बत पर अपने कब्जे को तेज करने और तिब्बत की अनूठी पहचान को नष्ट करने के लिए तुरंत तिब्बती लोगों पर अविश्वसनीय अत्याचार करने शुरू कर दिए।'

भारत के सारनाथ में उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर त्संगटुक टोपला ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बती सरकार पर जबरन थोपा गया समझौता था।' उन्होंने कहा कि चीन अब 17 सूत्रीय समझौते को तिब्बत पर अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए और तिब्बत पर अपने दावों के लिए नैतिक और अंतरराष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए भी उद्धृत करता है।'

टोपला ने कहा कि लेकिन चीन ने 'तिब्बती लोगों की धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और आदतों' का सम्मान करने और उनके रक्षा करने के अपने वादे को जल्दी से तोड़ दिया। और इसलिए, परम पावन दलाई लामा ने 1959 में भारत के तेजपुर में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिए गए एक बयान में समझौते का खंडन किया था।

टूटे हुए वादे

तिब्बत में चीन की नीतियां और व्यवहार आज दिखाते हैं कि बीजिंग 70 साल पहले किए गए वादों से कितना आगे निकल गया है, वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत ने 21 मई को एक बयान में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सालगिरह को याद किया।

आईसीटी ने कहा, 'समझौते के बाद से सात दशकों में, चीनी सरकार ने एकतरफा रूप से तेजी से कठोर नीतियां लागू की हैं जो तिब्बती संस्कृति और धर्म को कमजोर करती हैं और तिब्बती लोगों को अभियक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करती हैं।'

अधिकार समूह ने कहा कि इसने तिब्बती भाषा के उपयोग को भी कमतर कर दिया है और तिब्बत के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर चीन का दावा किया है। दूसरी ओर, चीनी प्रवासियों की बढ़ती संख्या इस क्षेत्र में बाढ़ की तरह आ रही है।

आईसीटी ने कहा, चीन ने तिब्बत के स्वतंत्र इतिहास से इनकार किया है और निर्वासित दलाई लामा के मध्यम मार्ग नीति दृष्टिकोण को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। हालांकि मध्यम मार्ग दृष्टिकोण बीजिंग के शासन में रह रहे तिब्बतियों के लिए मजबूत भाषा अधिकारों सहित अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का आग्रह करते हुए चीन के एक हिस्से के रूप में तिब्बत की स्थिति को स्वीकार करता है।

आईसीटी ने कहा कि चीन के जनवादी गणराज्य ढांचे के भीतर सभी तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्ता की मांग करने की दलाई लामा की नीति न केवल उनके दूतों द्वारा चीनी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है, बल्कि बाद में सार्वजनिक भी की गई है।

उन्होंने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को परस्पर संतोषजनक समाधान के माध्यम से तिब्बती समस्या को हल करने की दलाई लामा की प्रतिबद्धता के बारे में मूर्ख नहीं बना सकता।

डराने-धमकाने की कोशिश

लंदन स्थित फ्री तिब्बत ने 25 मई के एक बयान में कहा कि चीनी अधिकारी अब तिब्बत में सुरक्षा उपायों को कड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चीन जुलाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ की ऐतिहासिक तारीख के करीब पहुंच रहा है।

अधिकार समूह ने कहा, 'यह कदम संभवतः तिब्बतियों को ऐसे समरोहों के दौरान अपने देश पर कब्जे का विरोध करने से डराने-धमकाने का एक प्रयास है।' समूह ने आगे कहा कि मध्य तिब्बत के दोर्जे ड्रैक मठ में तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों को हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां का समर्थन करने वाले बैनरों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

फ्री तिब्बत ने कहा कि तिब्बत की क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा में मठों में सैकड़ों अन्य लोगों को चीनी साम्यवाद और कानूनों के बारे में उनके ज्ञान पर परीक्षण किया गया। दूसरी ओर आगामी शताब्दी वर्ष की तैयारी को लेकर अप्रैल के अंत में 'चीनी सरकार और प्रचार का जश्न मनाते हुए बड़ी संख्या में सुलेख का जबरन निर्माण कराया गया।'

एक बयान में, जॉन जोन्स-अभियान और फ्री तिब्बत के अनुसंधान प्रबंधक ने कहा कि विश्व नेताओं को अब तिब्बती लोगों को लेकर मोलभाव का रुख नहीं अपनाना चाहिए और न ही तिब्बत के धीरे-दीरे मानविकी से मिटा दिए जाने तक हाथ पर हाथ रखकर खड़े देखते रहना चाहिए।'

जॉस ने कहा कि बीजिंग द्वारा तिब्बत का दमन और उसके बारे में सच्चाई को अवरुद्ध करने के प्रयास 'तेजी से बदतर हो जाएंगे जब दुनिया की निगाहें 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए चीन पर होंगी।'

उन्होंने कहा, 'अगर दुनिया के देश चीन के इन अत्याचारों की लीपापोती करने से बचना चाहते हैं तो उन्हें अगले साल बीजिंग में एथलीटों को भेजने की अपनी योजना बदलनी चाहिए और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीतकालीन खेलों का बहिष्कार करना चाहिए।'

इस साल ओलंपिक के बहिष्कार को लेकर आवाज तेज हुई है। आलोचकों ने न केवल तिब्बत का हवाला दिया, बल्कि निकटवर्ती डिझिनियांग में उग्यूर तथा अन्य तुर्क मुसलमानों की सामूहिक कैद और बीजिंग द्वारा जुलाई-2020 के मध्य में हांगकांग में घोर दमन के लिए बनाए गए कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का भी हवाला दिया है।

दलाई लामा और उनके हजारों अनुयायी चीन के शासन के खिलाफ 1959 के असफल तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के बाद भारत और दुनिया के अन्य देशों में निर्वासन में रह रहे हैं।

चीनी अधिकारियों ने इस क्षेत्र पर अपनी कड़ी पकड़ बनाए रखी, तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की शांतिपूर्ण अभियक्ति को प्रतिबंधित किया और तिब्बतियों को चीनी उत्पीड़न, यातना, कारावास और न्यायेतर हत्याओं का दंश झेलना पड़ रहा है।

आरएफए की तिब्बती सेवा द्वारा रिपोर्ट। तेनजिन डिकी द्वारा अनुवाद। द। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लेखन। ◆